

मनरेगा जॉब कार्डों को नरिस्त किया जाना

प्रलिस के लयि:

[मनरेगा](#), [मनरेगा योजना](#), [नगर नगिम](#), [प्रबंधन सूचना प्रणाली](#), [आधार-आधारति भुगतान प्रणाली](#), [काम करने का कानूनी अधिकार](#), [बेरोज़गारी](#), [ग्राम पंचायत](#), [बेरोज़गारी भतता](#) ।

मुख्य परीक्षा के लयि:

गरीबी, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, वकिस से संबंघति मुद्दे, मनरेगा और संबंघति मुद्दे ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्योँ?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम, 2005 (मनरेगा) के अंतरगत जॉब कार्डों से शर्मकिों के नाम वलिोपति कयि जाने की हालयिा वृद्धतिने काम के अधिकार और कारयान्वयन में पारदर्शतिा को लेकर गंभीर चतिाएँ उत्पन्न कर दी हैं ।

- अकेले वर्ष 2022-23 में 5.53 करोड से अधिक शर्मकिों को हटा दयिा गया, जो वर्ष 2021-22 से 247% की वृद्धतिदर्शतिा है ।

मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के लयि मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- वलिोपन के आधार:** मनरेगा अधनियिम, 2005 की अनुसूची II, पैराग्राफ 23 के अनुसार, जॉब कार्ड को केवल वशिषिट, सुपरभिषति शर्तों के तहत ही हटाया जा सकता है:
 - स्थायी प्रवास: यदकि कोई परवार संबंघति [ग्राम पंचायत](#) से **स्थायी रूप से स्थानांतरति** हो जाता है ।
 - डुप्लीकेट जॉब कार्ड: यदकि कोई जॉब कार्ड **डुप्लीकेट** पाया जाता है ।
 - जाली दस्तावेज़: यदकि जॉब कार्ड **जाली दस्तावेज़ों** के आधार पर जारी कयिा गया हो ।
 - क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण: यदकि किसी ग्राम पंचायत को [नगर नगिम](#) के रूप में पुनर्वर्गीकृत कयिा जाता है, तो उससे संबंघति सभी जॉब कार्ड हटा दयिे जाते हैं ।
 - अन्य वैध कारण: मनरेगा [प्रबंधन सूचना प्रणाली \(MIS\)](#) में "डुप्लीकेट आवेदक", "फेक आवेदक" और "काम करने के लयि इच्छुक नहीं" जैसे कारण सूचीबद्ध हैं ।
- ABPS की भूमकिा:** वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड वलिोपन में वृद्धति अनविरय [आधार-आधारति भुगतान प्रणाली \(ABPS\)](#) के कारयान्वयन के साथ हुई, जसिके तहत शर्मकिों को अपने आधार नंबर को अपने जॉब कार्ड से जोडना आवश्यक हो गया ।
 - जनि शर्मकिों के आधार कार्ड **लकि नहीं थे या गलत तरीके से लकि थे**, उनके जॉब कार्ड नरिस्त कर दयिे गए ।
- वलिोपन की उच्चति प्रकरयिा:** वलिोपन के लयि प्रस्तावति शर्मकिों की **सुनवाई** दो स्वतंत्र वयक्तयिों की उपस्थति में की जानी चाहयिे, **हटाने के कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहयिे**, कारयवाही का **दस्तावेज़ीकरण कयिा जाना चाहयिे**, तथा पारदर्शतिा के लयि रिपोर्ट ग्राम सभा या वारड सभा के साथ साझा की जानी चाहयिे ।

नोट: एबीपीएस एक भुगतान प्रणाली है जो सरकारी सब्सडिी और लाभों को लाभार्थयिों के आधार से जुडे बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनकि रूप से भेजने के लयि आधार संख्यका उपयोग करति है ।

मनरेगा जॉब कार्डों के नरिस्त के क्या परिणाम होंगे?

- कार्य करने के अधिकार का उल्लंघन:** "कार्य करने के इच्छुक नहीं होने" के आधार पर जॉब कार्ड से शर्मकिों के नाम हटाना, शर्मकि के कार्य करने के उसके वधिकि अधिकार से वंचति करना है ।
 - जनि शर्मकिों पर "कार्य करने के लयि तैयार नहीं" के रूप में चहिनति कयिा गया था, उनमें से कई ने वास्तव में अपने हटाए जाने के वत्तितीय

वर्ष में काम किया था या काम के लिये अनुरोध किया था।

- असंगत प्रक्रिया: केवल कुछ श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाने के लिये प्रयुक्त किया गया आधिकारिक कारण "ग्रामीण शहरी बन जाता है" अधिनियम की इस शर्त का खंडन करता है कि शहरी क्षेत्र में सभी जॉब कार्ड हटा दिए जाने चाहिये।
 - नाम हटाने में अक्सर ग्राम सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, जो अधिनियम का उल्लंघन है तथा कई श्रमिकों को उनकी जानकारी के बिना गलत तरीके से नाम हटा दिए जाते हैं।
- सत्यापन का अभाव: कई श्रमिक गलत तरीके से नाम हटाए जाने के शिकार हुए, जब हटाए जाने के कारणों की वैधता का आकलन करने के लिये किसी सत्यापन या विश्लेषण के बिना ही उनका नाम हटा दिया गया।
 - यद्यपि नाम हटाने की प्रक्रिया एमआईएस में दर्ज की जाती है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाम हटाने के कारणों, जिनमें 'कार्य करने के लिये तैयार नहीं होना' का कारण भी शामिल है, का कोई सत्यापन और विश्लेषण नहीं किया है।
- वंचित समुदाय पर प्रभाव: "कार्य करने के लिये तैयार नहीं होने" जैसे कारणों से श्रमिकों को हटाना, विशेष रूप से उच्च ग्रामीण बेरोज़गारी दरों के मद्देनजर, प्रत्यक्ष तौर पर उनके आजीविका के अवसरों को कम करता है।
- डेटा-संचालित चिंताएँ: डेटा से ज्ञात होता है कि विलोपन में वृद्धि एबीपीएस पर बढ़ते फोकस के साथ संरेखित है, जो यह दर्शाता है कि विलोपन वास्तविक कारणों के बजाय अनुपालन प्रोत्साहनों से प्रेरित हो सकता है।

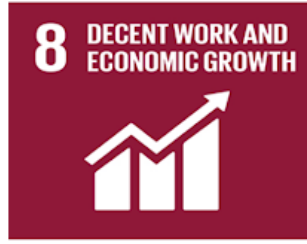
मनरेगा योजना क्या है?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया ताकमिनरेगा योजना के तहत रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।
- उद्देश्य: अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिवित्तीय वर्ष 100 दिनों का रोज़गार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है।
- पात्रता:
 - लक्षित समूह: रोज़गार की आवश्यकता वाले सभी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक, अकुशल कार्य करने के लिये तैयार हों।
 - पंजीकरण: आवेदक अपना आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा परिवारों को पंजीकृत करने के साथ सत्यापन के बाद जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
 - प्राथमिकता: वेतन चाहने वालों में कम से कम एक तहई महिलाएँ होनी चाहिये।
 - रोज़गार की शर्तें: रोज़गार कम से कम 14 दिनों तक लगातार चलना चाहिये तथा प्रति सप्ताह अधिकतम छह कार्यदिवस होने चाहिये।
- रोज़गार प्रावधान:
 - रोज़गार समयसीमा: ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन के 15 दिनों के अंदर आवेदक के गाँव के 5 किलोमीटर की सीमा में कार्य उपलब्ध कराना होता है।
 - 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर कार्य प्रदान करने की स्थिति में परविहन तथा अन्य लागत हेतु 10% अतिरिक्त वेतन का प्रावधान है।
 - बेरोज़गारी भत्ता: यदि 15 दिनों के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान है जो प्रथम 30 दिनों के लिये मजदूरी दर का एक-चौथाई तथा शेष के लिये कम से कम आधा होता है।
- अनुमेय कार्य:
 - जल एवं भूमि विकास: संरक्षण एवं संचयन।
 - वनरोपण एवं सूखा निवारण: वृक्षारोपण।
 - संचाई एवं कृषि अवसंरचना: नहरें, तालाब और संचाई।
 - ग्रामीण संपर्कता: सड़कें एवं पुलिया।
 - स्वच्छता एवं स्वास्थ्य: शौचालय तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
 - ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: सामुदायिक केंद्र एवं भंडारण केंद्र।
 - रोज़गार से संबंधित परियोजनाएँ: खाद बनाना, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन।
- प्रतिबंध: ठेकेदारों एवं श्रमिक-वसिस्थापन मशीनों का उपयोग नषिद्ध है।
- मनरेगा और सतत विकास लक्ष्य:

//



MGNREGs CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



आगे की राह

- **सत्यापन की प्रक्रियाएँ:** मनमाने ढंग से नाम हटाने की घटनाओं को कम करने तथा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयन में **मनरेगा अधिनियम, 2005** तथा **मास्टर सर्कुलर प्रोटोकॉल** का पालन किया जाए।
- **लेखापरीक्षा एवं नरीक्षण:** नरितरता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में समय-समय पर रिकॉर्ड में हेरफेर एवं जॉब कार्ड के नरिस्त होने के कारणों की लेखापरीक्षा करने हेतु **स्वतंत्र नकियाँ या तीसरे पक्ष की एजेंसियों की** स्थापना करनी चाहिये।
- **शिकायत नविवारण:** श्रमिकों को शिकायत दर्ज करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों के लयिनविवारण की मांग करने हेतु एक **स्पष्ट और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने हेतु प्रणालियों का नरिमाण या सुदृढीकरण करना।**
- **ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना:** यह सुनिश्चित करना कि सभी वल्लोपनों की समीक्षा की जाए और **ग्राम सभा द्वारा अनुमोदति किया जाए**, जैसा कि मनरेगा अधिनियम, 2005 में अनविवार्य किया गया है।
- **MIS को उन्नत करना:** **जॉब कार्ड** को सटीक रूप से ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने के लिये MIS को बेहतर नगरानी के लिये वास्तवकि समय अधिसूचना एवं सख्त रपौरटगि सुवधियों के साथ उन्नत बनाना।
 - समय पर **हस्तक्षेप** और सुधारात्मक कार्रवाई के लिये **जॉब कार्ड को नरिस्त करने** की प्रवृत्तियों और अनयिमतिताओं का पता लगाने के लिये डेटा वशिलेषण का उपयोग करना।

???????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: मनरेगा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ बनाकर मनमाने ढंग से कार्ड को नरिस्त करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

?????????:

प्रश्न. 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में नमिनलखिति में से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है? (2017)

1. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हसिसेदारी में भारी वृद्धि हुई ।
2. वशिव वयापार में भारत के नरियात का हसिसा बढा ।
3. FDI प्रवाह बढा ।
4. भारत के वदिशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई ।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात के परवारों के वयस्क सदस्य ।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परवारों के वयस्क सदस्य ।
- (C) सभी पछिडे समुदायों के परवारों के वयस्क सदस्य ।
- (D) कसिी भी घर के वयस्क सदस्य ।

उत्तर: (D)

???????

प्रश्न: "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबति नहीं हुई है ।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजएि तथा स्थति में सुधार के लयि अपने वचिर प्रस्तुत कीजयि । (2017)

प्रश्न: क्या कमजोर और पछिडे समुदायों के लयि आवश्यक सामाजकि संसाधनों को सुरक्षति करने के द्वारा, उनकी उन्नत के लयि सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहषिकृत कर देती हैं ? (2014)